

यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल विकास, टिहरी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी कसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल विकास, टिहरी के माह 12/2016 से 10/2017 तक के लेखा अ भलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री खुसी राम, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 15.11.2017 से 25.11.2017 तक श्री दानिश इकबाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मक:- इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री संदीप कुमार गर्ग सहायक लेखा परीक्षा अ धकारी तथा श्री महेश चन्द पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 30.12.2016 से 10.01.2017 तक श्री अ वनाश चन्द कटियार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में संपादित किया गया था। जिसमें माह 04/2014 से 11/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जाँच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2016 से 10/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जाँच की गयी।

2. (I) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अ धकार क्षेत्र:-

(अ) जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल विकास, टिहरी का मुख्य कार्यकलाप जनपद में संचालित बाल परियोजनाओं के संचालन में मुख्यालय द्वारा दिये गए निर्देशों/आदेशों का प्रभावी क्रयान्वयन एवं उचित मार्गदर्शन।

(ब) जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल विकास, टिहरी एवं इकाई द्वारा संचालित योजनाओं का भौगोलिक क्षेत्र समस्त हरिद्वार के विकास खण्ड में स्थित है।

(II) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अ धक्य (+)	बचत (-) समर्पण
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15			1803.31	1601.84	1587.59	1513.18		275.88
2015-16	--	--	33.88	26.93	258.23	257.19	--	7.99
2016-17	--	--	28.82	24.15	29.34	29.20	--	4.81
2017-18 (up to Nov. 2017)	--	--	23.88	21.32	0.21	0.14	--	2.63

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय	आ धक्य (+)	बचत/समर्पण (-)
2015-16	कशोरी शक्ति	00	शून्य	00	00	00
2016-17	कशोरी शक्ति	00	शून्य	220000	00	220000
2017-18 Nov. 2017	कशोरी शक्ति	220000	शून्य	00	00	220000
2015-16	आंगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण	00	00	00	00	64200000
2016-17	आंगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण	00	65000000	800000	00	64200000
2017-18 Nov. 2017	आंगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण	64200000	00	00	00	00
2015-16	निर्भया योजना	00	00	00	00	5070
2016-17	निर्भया योजना	00	602700	597630	00	88500
2017-18 Nov. 2017	निर्भया योजना	00	307500	219000	00	

(iii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्रोत निदेशक आई० सी० डी० एस० देहरादून एवं भारत सरकार से प्राप्त होते हैं। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

1. स चव
2. निदेशक
3. डी,पी,ओ,
4. सी.डी.पी.ओ
5. सुपरवाइजर
6. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, टिहरी को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, टिहरी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 06/2017 को वस्तुत जांच हेतु चयनित कया गया। जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, टिहरी का वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत कये गये व्यय जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, टिहरी के आधार पर कया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर 01: 16.23 लाख के अर्जित ब्याज की धनराश को शासन को प्रेषित न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक सं. 99/ xxvii (14) 2009 दिनांक 03.12.2009 के द्वारा ब्याज की धनराश को तत्काल 0049 लेखा शीर्ष में जमा कर दिया जाना चाहिए। यदि कसी मद में ब्याज की धनराश को व्यय किया जाना हो तो वक्त वभाग से पृथक शासनादेश उपलब्ध होना चाहिए तथा उस धनराश को आगामी वर्षों में समायोजित करते हुये शेष धनराश की मांग शासन से की जाएगी।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधकारी बाल विकास टिहरी के योजनाओं के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वभाग को आबंटित धनराश पर बैंक के द्वारा ब्याज दिया जाता है, वर्ष 2016-17 से 2017-18 (अक्टूबर 2017 तक) की अवधि में प्राप्त ब्याज की राश को 0049 में जमा न करने या धनराश को आगामी वर्षों में समायोजित करते हुये शेष धनराश की मांग शासन से नहीं किए जाने से ब्याज की धनराश रूप 16,22,610.00 लम्बित हैं, जिसे तत्काल 0049 लेखा शीर्ष में जमा कर दिया जाना चाहिए, ब्याज की राश का ववरण निम्नानुसार है:-

उपरोक्त ववरण से स्पष्ट है कि बैंक में ब्याज की धनराश प्रति वर्ष बढ़ रही थी तथा वभाग द्वारा ब्याज की धनराश रूप 16.23 लाख को शासन को वापस नहीं किया गया था, जो शासनादेश के प्रति उदासीनता को प्रकट करती है।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर वभाग ने अवगत कराया कि वभाग द्वारा उक्त धनराश को अ वलंब जमा करा दिया जायेगा।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि एक वर्ष बीत जाने के पश्चात भी वभाग द्वारा शासन को धनराश वापस नहीं की गयी। जिससे न केवल उक्त धनराश अनावश्यक रूप से अवरुद्ध है, जिसका विकास कार्यों पर उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका। अतः वभाग द्वारा रु. 16.23 लाख के अर्जित ब्याज की धनराश को शासन को प्रेषित न किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 01: धनराश रुपए 94.50 लाख की लागत से बनने वाले 21 आगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य अपूर्ण रहना तथा अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त रहना।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा भवन वहीन आगंबाड़ी केन्द्रों के लए पक्का भवन बनाए जाने के लए राज्य सरकारों से कार्ययोजना बनाने हेतु निर्देशित किया गया था (दिसंबर 2012), इस क्रम में उत्तराखण्ड में 1450 नए केन्द्रों का निर्माण व 113 केन्द्रों का उच्चीकरण हेतु राज्यांश रुपए 1659.50 लाख व केंद्रांश रुपए 4978.50 कुल रुपए 6638.00 लाख की वृत्तीय स्वीकृति प्रदान की थी, (उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 151 /XVII (4)/2015/2 (13) 2013 दिनांक 16.02.2015) इसी क्रम में निदेशालय आई० सी०डी०एस० उत्तरखंड देहरादून के पत्रांक 3606 दिनांक 23.02.2015 द्वारा (सामान्य) अनुदान संख्या 15 के अन्तर्गत जनपद टिहरी हेतु 54 नए आगंबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु रुपए 4.50 लाख की दर से रुपए 243.00 लाख तथा 09 केन्द्रों के उच्चीकरण हेतु रुपए एक लाख की दर से रुपए 09 लाख कुल रुपए 252.50 लाख तथा पत्रांक 3609 दिनांक 23.02.2015 द्वारा (अनुसूचित जाति) अनुदान संख्या 30 के अन्तर्गत 05 नए आगंबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु रुपए 4.50 लाख की दर से रुपए 22.50 लाख की वृत्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए उतनी ही धनराश निर्गत हुई थी।

ज़िला कार्यक्रम अधिकारी, टिहरी के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जनपद टिहरी में कुल 1278 आगनवाड़ी केंद्र तथा 739 मनी केंद्र स्वीकृत थे जिसके सापेक्ष 1265 आगनवाड़ी केंद्र तथा 693 मनी केंद्र संचालित हो रहे थे। 1265 आगनवाड़ी केंद्र एवं 693 मनी केंद्र के सापेक्ष 488 केंद्र करार के भवन में संचालित थे तथा 430 केन्द्रों को अन्य भवन के रूप में दर्शाया गया था शेष 880 केंद्र वभागीय अथवा शासकीय भवन में संचालित हो रहे थे। जांच में पाया गया कि जनपद में 59 आगंबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु 4.50 लाख लाख की दर से रुपए 265.50 लाख की धनराश, प्राप्ति तिथि के 2 माह बाद विकास खंडों को हस्तांतरित की गयी थी, ववरण निम्नवत था -

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	बाल विकास परियोजना का नाम	केन्द्रों की संख्या	दिनांक	धनराश (लाख में)
1	चम्बा	चम्बा	06	19.05.2015	27.00
2	प्रताप नगर	प्रताप नगर	06	19.05.2015	27.00
3	हिंडोलाखाल	हिंडोलाखाल	06	19.05.2015	27.00
4	भलंगना	भलंगना	08	19.05.2015	36.00
5	थौलधार	थौलधार	06	19.05.2015	27.00
6	थत्यूड	थत्यूड	06	19.05.2015	27.00
7	कीर्तिनगर	कीर्तिनगर	06	19.05.2015	27.00

8	जाखड़ीधार	जाखड़ीधार	06	19.05.2015	27.00
9	नरेन्द्र नगर	नरेन्द्र नगर	09	19.05.2015	40.50
			59		265.50

आगे जांच में पाया गया कि धनराशि निर्गत करने के 30 माह बाद भी सम्प्रेक्षा तिथि तक (11/2017) 59 में से 21 आगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य न केवल अपूर्ण था अपितु अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त थी।

उपरोक्त ववरण से स्पष्ट है कि वभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के आभाव में 75% भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित योजना आगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि रूपरेखा 265.50 लाख की धनराशि व्यय के बाद भी रूपरेखा 94.50 लाख की लागत के 21 आगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य 30 माह का समय बीतने के बाद भी न केवल अपूर्ण अपितु अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त थी, जबकि जनपद में 488 आगनवाड़ी केन्द्र कराए के भवन में संचालित थे। आगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण में हो रहे विलम्ब के कारण सरकार को अनावश्यक रूप से कराए के रूप में अतिरिक्त व्ययभार वहन करना पड़ रहा था, जो कि सरकार की अप्रत्यक्ष रूप से हानि थी।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर वभाग ने अवगत कराया कि कार्यदायी संस्था खण्ड विकास अधिकारी है जो मनरेगा के सहयोग से निर्माण कार्य करा रहे हैं मनरेगा की धनराशि समय पर उपलब्ध न होने के कारण भवन निर्माण में विलम्ब हो रहा है।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि धनराशि रूपरेखा 94.50 लाख की लागत से बनने वाले 21 आगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य 30 माह का समय बीतने के बाद भी न केवल अपूर्ण था अपितु अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त थी, जबकि जनपद में 488 आगनवाड़ी केन्द्र कराए के भवन में संचालित थे।

अतः धनराशि रूपरेखा 94.50 लाख की लागत से बनने वाले 21 आगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य 30 माह का समय बीतने के बाद भी अपूर्ण रहने था तथा अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 02: कशोरी शक्ति की धनराश ₹ 2.20 लाख को अवरुद्ध रखा जाना ।

भारत सरकार की दिशा निर्देशानुसार राज्य में कशोरी शक्ति योजना 09 जनपदों के कुल 70 परियोजनाओं में संचालित है इस योजना के अन्तर्गत i) 11-18 वर्ष की कशोरियों के स्वास्थ्य तथा पोषण के स्तर में सुधार लाना। ii) अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से कशोरी बालिकाओं को अपेक्षित साक्षरता एवं अंकीय ज्ञान प्रदान करना। iii) कशोरी बालिकाओं में गृह-आधारित एवं व्यावसायिक कौशलों का सुधार करना। iv) समाज के उत्पादक और उपयोगी सदस्य के रूप में व भन्न गति व धियां आयोजित करने के लिए कशोरियों को प्रोत्साहित करना। निदेशालय के पत्र संख्या सी 2567/2982(QPR-ksy) 2014-15 दिनांक 14.12.2014 में इस सम्बंध निर्देश दिया गया है कि कशोरी शक्ति योजना की कार्य योजना बनाते हुये योजना का क्रयान्वयन किया जाए तथा योजना के क्रयान्वयन की मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट तथा प्रमाण पत्र निदेशालय को उपलब्ध करायेगा।

निदेशालय के पत्र क्रमांक सी 2846/ बजट- 4073/2016-17 दिनांक 27.02.2017 को वृत्तीय स्वीकृति रूपर 7700000/- के सापेक्ष रूपये 1980000/- का आबंटन किया गया जिसमें जनपद टिहरी के लिए धनराश रूपये 220000/- की धनराश जारी की गयी। जिस मद में आबंटित धनराश का व्यय न हो/ बचत हो को दिनांक 31 मार्च 2017 तक व्यय आगणत कर बचत राश का समर्पण कोषागार के माध्यम से तत्काल मुख्यालय को करना सुनिश्चित करें। कशोरियों के व्यावसायिक कौशल विकास निर्माण के लिए बैंक/पोस्ट ऑफिस/स्थानीय स्तर पर उपलब्ध व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र/कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र आदि से संबन्धित जानकारीयां प्रदान की जानी थीं।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधकारी बाल विकास, टिहरी की कशोरी शक्ति योजना के नमूना जांच के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वभाग को वर्ष 2016-17 के लिए प्राप्त धनराश रूपये 220000/- से कार्य योजना को तैयार कर योजना के क्रयान्वयन के लिए कार्यवाही की जानी थी लेकिन वभाग द्वारा न तो योजना की कार्य योजना को बनाने की कार्यवाही की गयी और न ही योजना के क्रयान्वयन हेतु कोई कार्यवाही की गयी।

उक्त ववरण से स्पष्ट है कि वभाग की उदासीनता के कारण योजना की कार्य योजना को बनाने की कार्यवाही की गयी और न ही योजना के क्रयान्वयन की मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट तथा उपभोग प्रमाण पत्र निदेशालय को उपलब्ध कराई गई तथा धनराश रूपर 2.20 लाख को जिला कार्यक्रम अधकारी के पद नाम खाते में अवरुद्ध रखा गया।

उक्त के सम्बंध इंगत किए जाने पर जिला कार्यक्रम अधकारी ने अवगत कराया कि धनराश मार्च 2017 में प्राप्त हुई थी जिस कारण कार्य किए जाने की औपचारिकताएं पूर्ण नहीं हो पायीं

धनरा श आहरित कर डीपीओ पद नाम खाते में जमा थी, औपचरिकताए पूर्ण कर व्यय की कार्यवाही की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्यों क निदेशालय के यह स्पष्ट निर्देश थे क जिस मद में आबंटित धनरा श का व्यय न हो / बचत हो को दिनांक 31 मार्च 2017 तक व्यय आग णत कर बचत रा श का समर्पण कोषागार के माध्यम से तत्काल मुख्यालय को करना सुनिश्चित कया जाना था तथा वभाग की उदासीनता के कारण योजना की कार्य योजना को बनाने की कार्यवाही की गयी और न ही योजना के क्रयान्वयन की मा सक / त्रैमा सक रिपोर्ट तथा उपभोग प्रमाण पत्र निदेशालय को उपलब्ध कराये गये।

अतः कशोरी शक्ति की धनरा श ₹ 2.20 लाख को अवरुद्ध रखने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 03: मानव संसाधन प्रबंधन तथा योजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन नहीं किया जाना।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ, जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के माध्यम से आगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा क्रयान्वयन किया जाता है, योजनाओं से संबन्धित धनराशि बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित कर आगनवाड़ी कार्यकर्ता के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाता है। संचालित योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का उत्तरदायित्व जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं सुपरवाइजर का होता है।

निदेशालय, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 196-97 दिनांक 21.5.2002 द्वारा आगनवाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण के सम्बंध में दिशानिर्देश जारी किया गया था, उक्त के अनुसार विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं के अनुश्रवण हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी को माह 5 से 10 दिन बाल विकास परियोजना अधिकारी को 10 से 15 दिन तथा मुख्य से वका (सुपरवाइजर) को 15 से 20 दिन प्रति माह भ्रमण किया जाना अनिवार्य होगा।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग टिहरी के अन्तर्गत संचालित योजनाओं एवं उसके निष्पादन हेतु जनपद में जिला कार्यक्रम अधिकारी का 01 पद, बाल विकास परियोजना अधिकारी के 09 पद तथा सुपरवाइजर के 50 पद स्वीकृत हैं। जांच में पाया गया कि जनपद टिहरी में जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर तैनात हैं जिनके पास 04 बाल विकास परियोजनाओं का भी चार्ज था, जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यभार के साथ साथ 04 बाल विकास परियोजना का कार्यभार वहन करना विशेषकर पहाड़ी क्षेत्र में कसी भी दशा में व्यावहारिक नहीं था। इसी प्रकार 09 बाल विकास परियोजना अधिकारी के सापेक्ष मात्र 01 पद पर तैनाती थी, जिनके पास 05 बाल विकास परियोजना का कार्यभार था, टिहरी जनपद की वषम भौगोलिक परिस्थिति में 05 परियोजनाओं का कार्यभार एवं उत्तरदायित्वों का पालन एक बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा करना संभव नहीं था, तथा शेष 08 पद रिक्त थे। 50 सुपरवाइसर के पद के सापेक्ष 40 पद पर तैनाती थी शेष 10 पद रिक्त थे। 25 आगनवाड़ी केन्द्रों पर एक सुपरवाइजर की तैनाती का प्रावधान है, जनपद टिहरी में 1958 (मुख्य केंद्र 1265 तथा मीनी 693) केंद्र संचालित हैं। 1958 केन्द्रों के सापेक्ष मात्र 40 सुपरवाइजर की तैनाती स्वतः प्रदर्शित करती है कि एक सुपरवाइसर को औसतन 49 केन्द्रों के पर्यवेक्षण का दायित्व था। एक सुपरवाइसर द्वारा एक माह में, पहाड़ी क्षेत्र में 49 आगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया जाना कसी भी दशा में संभव नहीं था, इससे स्पष्ट है कि आगनवाड़ी केन्द्रों का हर माह निरीक्षण नहीं किया जा रहा था। इकाई द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी की

निरीक्षण पंजिका का संधारण नहीं किया जा रहा था, जिससे परिलक्षित होता कि जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रति माह कितने दिन अपने क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा था। अभिलेखों को निर्धारित मानकों के अनुरूप क्षेत्र के भ्रमण का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं था।

उपरोक्त ववरण से स्पष्ट है कि जनपद टिहरी में, बाल विकास विभाग के अन्तर्गत स्टाफ की भारी कमी थी, आवश्यकतानुसार कर्मचारियों एवं अधिकारियों की तैनाती हेतु भी इकाई द्वारा कोई भी प्रयास नहीं किया गया था। विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन निर्धारित मानकों एवं प्रावधानों के अंतर्गत नहीं किया जा रहा था।

उक्त के सम्बंध में इंगत किए जाने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी ने अवगत कराया कि जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा प्रति माह 03 केन्द्र का भ्रमण किया गया जनपद में बाल विकास परियोजना अधिकारी के 01 पद एवं सुपरवाइजर के 10 पद रिक्त होने पर कार्यरत सुपरवाइजरों के माध्यम से ही कार्य लए जा रहे जिस कारण योजनाओं के अनुश्रवण व मूल्यांकन पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि जिला कार्यक्रम अधिकारी के अन्तर्गत कार्यालय में स्टाफ की भारी कमी थी, आवश्यकतानुसार कर्मचारियों एवं अधिकारियों की तैनाती हेतु भी इकाई द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया था। विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन निर्धारित मानकों एवं प्रावधानों के अंतर्गत नहीं किए जा रहे थे।

अतः मानव संसाधन प्रबंधन तथा योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन नहीं किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या	स्टेन
55/2012-13	शून्य	01	शून्य
08/2014-15	शून्य	02	02
125/2016-17	शून्य	1,2,3	शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
55/2012-13	01	भाग-दो (ब)	यथावत	
08/2014-15	02 02	भाग-दो (ब) STAN	यथावत	
125/2016-17	1,2,3,4	भाग-दो (ब)	यथावत	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-----शून्य-----

भाग-Vआभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, टिहरी तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये:
 - (I) शून्य
3. सतत् अनिय मतताएं
 - (I) शून्य
4. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अव ध
1.	श्री वक्रम सिंह	जिला कार्यक्रम अ धकारी	22/11/2014 से वर्तमान तक

(V) लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, टिहरी को इस आशय से प्रेषित कया गया क वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी सा.क्षे.